covered by TV service. On implementation of the various Seventh Plan Schemes of Doordarshan, all the aforesaid uncovered districts are expected to be covered by TV service, either wholly or partially.

Action against blackmarketeers and hoarders

2120. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what are the names of the States which have taken action against blackmarketeers and hoarders of essential commodities under the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act in the last three years; and

(b) what are the details of the steps taken so far by the State Governments concerned?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) and (b) According to information available, action taken by the States under the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 during the last three years is given in enclosed Statement.

Statement

Sl.No.	States/UTs.	No. of persons ordered to be detained		
		1985	1986	1987 (upto 23-11-1987)
1	Andhra Pradesh	17	17	30
2	Assam	3	..	..
3	Bihar	..	4	3
4	Gujarat	35	53	110
5	Madhya Pradesh	21	1	3
6	Maharashtra	5	4	3
7	Orissa	4	2	2
8	Tamil Nadu	..	5	..
9	Uttar Pradesh	14	..	2
	TOTAL :	100	86	153

राजस्थान में मरूभूमि परिसर

2121. **श्री भंवर लाल पंवार :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में मरूभूमि परिसर के संबंध में मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन को कब सौंपा गया था ;

(ख) क्या आर्गेनाइजेशन ने राज्य सरकार और पर्यटन विभाग के परामर्श से मास्टर प्लान तैयार कर लिया है ;

(ग) क्या मास्टर प्लान के अनुरूप कार्य का कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया गया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कब तक आरम्भ कर दिये जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या मरूभूमि परिसर योजना में वर्तमान यातायात व्यवस्थाओं के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने

का उपबन्ध है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राजस्थान में मरूभूमि परिसर का मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य नगर तथा ग्राम संगठन को नहीं सौंपा गया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Jerseys purchased for the staff of DDA

2122. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item captioned "DDA mein lakhon rupaye ki Jarsion ki Dhandli" as reported in the Nav Bharat Times dated the 25th October, 1987;

(b) if so, whether it is a fact that the Jerseys procured by the DDA from the different agents are sub-standard and even the colours of the jerseys have faded; and

(c) the steps Government propose to take against those who are involved in such fictitious deals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The D.D.A. have denied this.

(c) Does not arise in view of (b) above.

Housing by non-resident Indians

2123. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Non-resident Indians (NRIs) have been permitted by Government to construct houses in the country;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) to what extent the steep problem of housing in the country is likely to be solved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) Government have not permitted Non-Resident Indians (NRIs) to invest in Housing construction on a commercial basis. The question of the impact of such investment on the problem of housing in the country does not, therefore, arise.

उत्तर प्रदेश में कस्बों और शहरों का विकास

2124. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में कस्बों तथा शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा धनराशियों का आवंटन किया जाता है; यदि हां, तो इसके क्या आधार तथा मानदंड हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और 1987-88 के लिए कितना प्रावधान किया गया है; और

(ग) इस धनराशि का किन-किन स्थानों पर कितना और किस प्रकार से उपयोग किया गया ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास